दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

ख़बर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। देश की राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, 6 और 7 सितंबर को किसी बड़े मंत्रिमंडलीय बदलाव की संभावना संबंधी अटकलों पर सरकार अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद देश लौटे। इसके पश्चात 2 सितंबर को उन्होंने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय विभागीय जल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लिया। आधिकारिक कार्यक्रमों के बीच संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। फेरबदल की अटकलों को क्यों मिल रहा बल? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावना को कई कारणों से बल मिल रहा है। आगामी चुनावों, राज्यों के राजनीतिक समीकरणों, एनडीए सहयोगी दलों की अपेक्षाओं और विभिन्न मंत्रालयों में

कार्यभार के संतुलन जैसे मुद्दों को इस चर्चा का आधार माना जा रहा है। हाल के महीनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जुलाई 2026 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति के आदेश से शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्राद जोशी को सौंपा गया था। इस घटनाक्रम के बाद संभावित व्यापक फेरबदल की राजनीतिक चर्चाएं और तेज हुई हैं। युवा चेहरे और क्षेत्रीय संतुलन पर नजर राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि मंत्रिमंडल में विस्तार अथवा फेरबदल होता है तो सरकार युवा नेताओं, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि, नए मंत्रियों के नामों अथवा किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद रवि किशन सहित विभिन्न नेताओं के नामों को लेकर चल रही चर्चाएं फिलहाल राजनीतिक अटकलों के दायरे में हैं। कई मंत्रियों के पास हैं अतिरिक्त विभाग मौजूदा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के पास एक से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भविष्य में किसी फेरबदल की स्थिति में अतिरिक्त विभागों का पुनर्वितरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का विवरण समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्तमान में प्राद जोशी के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दर्ज है। एनडीए सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण संभावित मंत्रिमंडलीय बदलाव की चर्चा में एनडीए के सहयोगी दलों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार में सहयोगी दलों की राजनीतिक हिस्सेदारी और राज्यों के बदलते समीकरण भविष्य के किसी भी विस्तार या फेरबदल में प्रभाव डाल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और एनडीए नेतृत्व प्रतिनिधित्व के संतुलन पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत अथवा घोषणा सामने नहीं आई है। 6 और 7 सितंबर पर नजर, लेकिन पुष्टि का इंतजार राजनीतिक हलकों में 6 और 7 सितंबर को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन इन तारीखों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के आगामी कार्यक्रमों के बीच संभावित राजनीतिक निर्णयों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़ी किसी भी खबर की पुष्टि केवल प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन अथवा मंत्रिमंडल सचिवालय की आधिकारिक घोषणा के बाद ही संभव होगी। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से होने वाली किसी भी आधिकारिक घोषणा पर देशभर की निगाहें टिकी रहेंगी।

बारिश अलर्ट से बढ़ी चिंता

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह, बेंगलुरु
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली-एनसीआर सहित कई इलाकों में मौसम का असर जनजीवन पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उपलब्ध मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 3 से 5 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव होने तथा सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी नवीनतम चेतावनियों पर नजर रखें। उत्तराखंड में विशेष सतर्कता जरूरी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम के कारण विशेष सावधानी की आवश्यकता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश, गरज-

चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज वर्षा के दौरान भूस्खलन, सड़क मार्ग बाधित होने और नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यात्रियों और स्थानीय निवासियों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। दिल्ली-एनसीआर में भी बदला मौसम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भी बारिश का दौर बना हुआ है। 3 और 4 सितंबर के दौरान कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि अगले दिन भी मौसम में बदलाव जारी रहने का अनुमान है। बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन, जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। स्कूल, कार्यालय अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को मौसम और यातायात की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। गरज-चमक के दौरान बरतें सावधानी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों में खड़े होने से बचना चाहिए। पेड़ों, बिजली के खंभों और अन्य जोखिम वाले स्थानों से दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहता है। जलभराव वाले मार्गों से वाहन निकालने से बचना चाहिए तथा तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों से संपर्क करना उचित रहेगा। स्थानीय अपडेट पर रखें नजर उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी पूरी तरह समाप्त होने के संकेत नहीं हैं। हालांकि, वर्षा की तीव्रता और मौसम की स्थिति अलग-अलग जिलों एवं क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है।

दो दशक बाद बेल्जियम के पीएम भारत पहुंचे

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026।भारत और बेल्जियम के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है और करीब दो दशक बाद किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत-बेल्जियम संबंधों के विभिन्न आयामों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रक्षा मंत्री भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल बार्ट डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन भी भारत आए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री डी वेवर ने फरवरी 2025 में पदभार संभाला था और इसके बाद भारत की उनकी यह पहली यात्रा है। उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी को भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।व्यापार और निवेश पर रहेगा विशेष जोर भारत और बेल्जियम के बीच आर्थिक सहयोग लंबे समय से द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। दोनों

देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के अवसरों पर वार्ता में विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। हीरा कारोबार भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक प्रमुख क्षेत्र है। बेल्जियम का एंटवर्प विश्व के प्रमुख हीरा व्यापार केंद्रों में शामिल है, जबकि भारत हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर नजर दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बेल्जियम के रक्षा मंत्री का इस यात्रा में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को और महत्वपूर्ण बनाता है। भारत-ईयू एफटीए पर भी होगी चर्चा बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत यात्रा के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के कारोबारी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (इंडिया-ईयू एफटीए) से जुड़े मुद्दों और व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों के बीच इस यात्रा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स पर फोकस नई दिल्ली में आधिकारिक बैठकों के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री के मुंबई जाने का कार्यक्रम है। वहां वे हीरा उद्योग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबारी और आर्थिक सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। भारत-बेल्जियम रिश्तों को नई गति की उम्मीद भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक तथा आर्थिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा और जनसंपर्क के क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग का दायरा लगातार विकसित हुआ है।

सीपी इनर सर्किल होगा वाहनमुक्त?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com\

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। देश की राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र कनॉट प्लेस (सीपी) को अधिक पैदल यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने एक बार फिर पहल शुरू की है। एनडीएमसी इनर सर्किल में वाहनों की आवाजाही को सीमित करने अथवा निर्धारित समय के लिए इसे वाहनमुक्त क्षेत्र बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस संबंध में एनडीएमसी की ओर से व्यापारियों, स्थानीय हितधारकों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के तहत मौसम के अनुसार नो-व्हीकल जोन का समय निर्धारित करने और सप्ताहांत में इसकी अवधि बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सीधे लागू करने के बजाय सुझावों पर जोर कनॉट प्लेस के इनर सर्किल को वाहनमुक्त बनाने की कवायद पहले भी विभिन्न अवसरों पर सामने आ चुकी है। पूर्व में योजना और परीक्षण किए गए, लेकिन पार्किंग, यातायात और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह व्यवस्था स्थायी रूप से लागू नहीं हो सकी। इस बार एनडीएमसी सीधे किसी व्यवस्था को लागू करने के बजाय पहले सभी संबंधित पक्षों की राय लेने की रणनीति अपना रही है। अधिकारियों के अनुसार मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग समय में वाहनों की आवाजाही सीमित करने के विकल्प

पर विचार किया जा सकता है। गर्मी में शाम, सर्दी में दिन का विकल्प प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गर्मियों के मौसम में शाम के समय इनर सर्किल को वाहनमुक्त रखने का विकल्प विचाराधीन है। वहीं, सर्दियों में दिन के समय पैदल यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था बनाई जा सकती है। सप्ताहांत के दौरान नो-व्हीकल जोन की अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कनॉट प्लेस में पैदल चलने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना तथा क्षेत्र में लोगों के ठहराव और सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सेंट्रल पार्क बनेगा गतिविधियों का केंद्र एनडीएमसी की योजना केवल वाहनों की आवाजाही सीमित करने तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। प्रस्तावित वाहनमुक्त अवधि के दौरान इनर सर्किल और सेंट्रल पार्क में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। संगीत कार्यक्रम, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, कला प्रदर्शनियां, योग गतिविधियां, बच्चों के लिए कार्यक्रम और हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन संभावित विकल्पों में शामिल हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य कनॉट प्लेस को केवल खरीदारी और व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय एक जीवंत सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करना है। व्यापारियों की चिंताएं भी अहम वाहनमुक्त क्षेत्र की योजना के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती स्थानीय व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों की चिंताओं को दूर करना है। पहले भी व्यापारियों ने आशंका जताई थी कि ग्राहकों के वाहनों की पहुंच सीमित होने से दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्राहकों की सुविधा, पार्किंग व्यवस्था और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव भी प्रमुख मुद्दे हैं। इसलिए एनडीएमसी के लिए व्यापारिक गतिविधियों और पैदल यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। पार्किंग और यातायात प्रबंधन पर रहेगा फोकस यदि योजना लागू की जाती है तो वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाना आवश्यक होगा। टैक्सी और ऑटो के लिए निर्धारित पिक-एंड-ड्रॉप प्वाइंट, आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध रास्ता तथा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही आसपास की सड़कों पर वाहनों का अतिरिक्त दबाव न बढ़े, इसके लिए समग्र यातायात योजना तैयार करनी होगी। ट्रायल के बाद तय हो सकती है आगे की रणनीति हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एनडीएमसी पहले सीमित अवधि के लिए परीक्षण व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकती है। इस दौरान पैदल यात्रियों की संख्या, व्यापारिक गतिविधियों, पार्किंग व्यवस्था और यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त और ऐतिहासिक व्यावसायिक क्षेत्र में किसी भी बड़े बदलाव के लिए स्थानीय जरूरतों और जनसुविधा के बीच संतुलन आवश्यक है।

रासपुतिन गाने पर सिंघवी की चुटकी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। मुलाकात से जुड़े एक वीडियो में इस्तेमाल किए गए संगीत को लेकर कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा अध्यक्ष पर कटाक्ष किया है। राजदूत डेनिस अलीपोव ने 1 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन से मुलाकात की थी। बैठक में भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। रूसी दूतावास ने भी बैठक की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जानकारी दी है। वीडियो के संगीत पर उठाया सवाल नितिन नवीन ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में रूस से जुड़े लोकप्रिय गीत रा रा रासपुतिन का संगीत इस्तेमाल किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने टिप्पणी की। सिंघवी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे हास्यास्पद बताया और कहा कि रूसी राजदूत से मुलाकात के दौरान इस गीत का इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। नितिन नवीन ने बताई बैठक की अहमियत नितिन नवीन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उन्हें भाजपा मुख्यालय में रूसी संघ के राजदूत डेनिस अलीपोव का स्वागत करते हुए खुशी हुई। उनके अनुसार, दोनों के बीच भारत और रूस के समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को लेकर सौहार्दपूर्ण एवं सार्थक बातचीत हुई। बैठक के दौरान भारत-रूस संबंधों को आगे मजबूत करने और दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी चर्चा की गई। भारत-रूस संबंधों पर केंद्रित रही बातचीत भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले के अनुसार, बैठक में भारत और रूस के दीर्घकालिक संबंधों पर चर्चा हुई। नितिन

नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच उच्चस्तरीय संवाद और आपसी विश्वास का उल्लेख करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मिली गति पर बात की। बैठक में हाल में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात का भी उल्लेख किया गया। साथ ही भविष्य में उच्चस्तरीय संपर्क और भारत में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भी चर्चा हुई। व्यापार और जनसंपर्क पर भी चर्चा रूसी दूतावास के अनुसार, दोनों पक्षों ने अंतर-पार्टी और अंतर-संसदीय संबंधों को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने तथा द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। बैठक में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के साथ-साथ लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने 2027 में भारत और रूस के राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे होने को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की भी दी जानकारी बैठक के दौरान नितिन नवीन ने भाजपा की संगठनात्मक यात्रा, जमीनी स्तर पर पार्टी की संरचना और कार्यप्रणाली की जानकारी भी साझा की। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यापक नेटवर्क, मोर्चों और विभागों तथा चुनावों के अलावा निरंतर संगठनात्मक गतिविधियों पर पार्टी के जोर का उल्लेख किया। बैठक से जुड़े आधिकारिक विवरण के अनुसार, राजदूत अलीपोव ने भारत में भाजपा की संगठनात्मक पहुंच और जमीनी स्तर पर सक्रियता की सराहना की। लोगों के साथ सीधे संवाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया। राजनीति से सोशल मीडिया तक पहुंची बहस रूसी राजदूत और भाजपा अध्यक्ष की मुलाकात मुख्य रूप से भारत-रूस संबंधों पर केंद्रित रही, लेकिन मुलाकात के वीडियो में इस्तेमाल किए गए संगीत ने राजनीतिक बहस को नया विषय दे दिया। अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणी के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भाजपा की ओर से सिंघवी की टिप्पणी पर तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर, भारत-रूस संबंधों पर हुई कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व की बैठक के साथ वीडियो के संगीत को लेकर उठी बहस ने इस मुलाकात को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है।

पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर ढहाने पर भारत सख्त, जांच की मांग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में एक सौ वर्ष से अधिक पुराने हिंदू मंदिर के ढहाए जाने की खबरों पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से घटना की तत्काल जांच कराने और अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नारोवाल के सिराज गांव स्थित ऐतिहासिक हिंदू पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यक समुदाय के करीब एक सदी पुराने धार्मिक स्थल के साथ कथित तोड़फोड़ की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। धार्मिक

स्थल की सुरक्षा पर उठे सवाल जायसवाल के अनुसार, किसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की सुरक्षा में स्थानीय प्रशासन की कथित विफलता गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने कहा कि ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और उनके पूजा स्थलों के संरक्षण को लेकर सवाल खड़े करती हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मंदिर गिराने की वजह पर अलग-अलग दावे लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर सिराज गांव में स्थित यह मंदिर 21 अगस्त को ढहाए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना को लेकर पाकिस्तान में अलग-अलग दावे सामने आए हैं। अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर की जमीन को कथित तौर पर पास स्थित मदरसे के परिसर में शामिल करने के उद्देश्य से इसे निशाना बनाया। हालांकि, पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) का दावा है कि भारी बारिश के कारण मंदिर की इमारत ढह गई। इन परस्पर विरोधी दावों के कारण घटना की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि मंदिर प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ या उसे जानबूझकर गिराया गया। अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार का मुद्दा भारत ने इस घटना को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों और पूजा स्थलों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक प्रश्न के रूप में उठाया है। नई दिल्ली का कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा संबंधित सरकार की जिम्मेदारी है और ऐतिहासिक पूजा स्थलों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जाना चाहिए। फिलहाल घटना की परिस्थितियों और मंदिर के ढहने के कारणों को लेकर पाकिस्तान की ओर से सामने आए दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। भारत ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर वह अपनी चिंता पाकिस्तान के समक्ष उठाता रहेगा।

नेपाल बाढ़ से काठमांडू संपर्क ठप

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नेपाल/महराजगंज, 3 सितंबर 2026। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति का असर अब देश की प्रमुख यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। त्रिशूली नदी के जलस्तर में वृद्धि और लगातार बारिश के कारण पृथ्वी राजमार्ग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचने की खबर है। सड़क धंसने और भूस्खलन के चलते काठमांडू को नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया है। धादिंग जिले के मलेखु क्षेत्र में सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे यात्रियों और मालवाहक वाहनों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, सड़क क्षति और यातायात बाधित होने की वास्तविक स्थिति तथा प्रभावित वाहनों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि संबंधित नेपाली प्रशासन की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर की जानी बाकी है। मलेखु क्षेत्र में सड़क धंसने से बढ़ी परेशानी स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार धादिंग जिले के मलेखु स्थित शीतल बाजार क्षेत्र में बाढ़ के दबाव के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। बताया जा रहा है कि करीब 60 मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कृष्णभीर और मलेखु के समीप अन्य स्थानों पर भी सड़क क्षति की सूचना है, जिसके कारण पृथ्वी राजमार्ग से आवागमन प्रभावित हुआ। यह मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू को देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग माना जाता है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन और यातायात एजेंसियों के सामने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बन गया है। तीन वैकल्पिक मार्गों से आवागमन की कोशिश मुख्य मार्ग

प्रभावित होने के बाद यात्रियों और वाहनों को उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जा रहा है। हेटौंडा-दामन-पालुंग-नौबिसे होते हुए जाने वाला त्रिभुवन राजपथ एक प्रमुख विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, इस मार्ग में अधिक मोड़ और भौगोलिक चुनौतियों के कारण यातायात क्षमता सीमित रहने की बात कही जा रही है। दूसरा मार्ग हेटौंडा-भीमफेदी-कुलेखानी होकर काठमांडू की ओर जाता है। संकरा होने के कारण इस मार्ग पर मुख्य रूप से हल्के वाहनों की आवाजाही अधिक उपयुक्त मानी जा रही है। तीसरे विकल्प के रूप में हेटौंडा-मकवानपुरगढ़ी-ठिंगन-छपेली होते हुए ललितपुर पहुंचने वाले मार्ग का उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यातायात को नियंत्रित करने और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। रसुवा जिले में बाढ़ और भूस्खलन का असर नेपाल के रसुवा जिले में भी बाढ़ और भूस्खलन से कई क्षेत्रों के प्रभावित होने की खबरें हैं। टिमुरे, रसुवागढ़ी, स्याफ्रूबेंसी, मैलुंग, बेट्रावती, धुन्चे और त्रिशूली क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक आपदा का प्रभाव बताया जा रहा है। तेज जलप्रवाह और मलबे के कारण कई जगहों पर सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और स्थिति का आकलन करने का कार्य स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, प्रभावित क्षेत्रों और नुकसान के विस्तृत आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक आपदा प्रबंधन एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर की आशंका नेपाल में प्रमुख सड़कों और परिवहन मार्गों के बाधित होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। गैस, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामानों की ढुलाई में देरी होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित होने पर राहत सामग्री पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में प्रशासन के लिए प्राथमिकता सड़क संपर्क बहाल करने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

बाढ़ और बारिश का कहर: चेतावनी से आगे कब बढ़ेगा भारत ?

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

देश के कई हिस्सों में इस समय बारिश राहत से अधिक चुनौती बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बाढ़ की स्थिति ने जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं देश के अनेक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। सड़कें जलमग्न हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, संपर्क मार्ग बाधित हो रहे हैं और हजारों परिवारों के सामने सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की चुनौती खड़ी है। बारिश प्रकृति का वरदान है, लेकिन जब वही बारिश आपदा का रूप ले ले तो प्रश्न केवल मौसम का नहीं रहता। सवाल यह होता है कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, शहरों की जल निकासी व्यवस्था कितनी सक्षम है, नदियों के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को हमने कितना सुरक्षित रखा है और आपदा आने से पहले प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है। आज भारत के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है—क्या हम हर वर्ष बाढ़ आने के बाद राहत बांटने की व्यवस्था को ही आपदा प्रबंधन मानते रहेंगे, या बाढ़ को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने की स्थायी नीति बनाएंगे?

बारिश नहीं, अव्यवस्था बनती है बड़ी आपदा

भारत में मानसून कोई नई घटना नहीं है। सदियों से देश में वर्षा होती रही है और नदियां उफनती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह कम समय में अत्यधिक वर्षा और अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने हमारी पारंपरिक तैयारी की कमियों को उजागर कर दी हैं। प्राकृतिक वर्षा को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम करना निश्चित रूप से संभव है। समस्या तब बढ़ती है जब नदियों के किनारे अनियोजित निर्माण होते हैं, जल निकासी के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तालाब और जलाशय समाप्त होते जाते हैं तथा शहरों में कंक्रीट का विस्तार पानी के प्राकृतिक रिसाव को रोक देता है। जब बारिश का पानी जमीन में नहीं उतर पाता और उसके निकलने के प्राकृतिक रास्ते भी अवरुद्ध होते हैं, तो कुछ घंटों की तेज बारिश भी शहर को जलभराव में बदल सकती है। इसलिए बाढ़ को केवल प्राकृतिक आपदा कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश से मिल रही बड़ी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बाढ़ की स्थिति इस बात का संकेत है कि नदी आधारित क्षेत्रों में मानसून प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। ताजा रिपोर्टों में चित्रकूट सहित कई इलाकों में हजारों लोगों के प्रभावित होने और राहत एवं निकासी की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है। जिनके घर कच्चे होते हैं, जिनकी आजीविका खेती या पशुपालन पर निर्भर होती है और जिनके पास वैकल्पिक आवास की सुविधा सीमित होती है, उनके लिए बाढ़ केवल कुछ दिनों की परेशानी नहीं होती। फसल नष्ट होने का अर्थ महीनों की आय का नुकसान है। पशुधन का नुकसान परिवार की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर सकता है। मकान क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्वास की समस्या अलग खड़ी हो जाती है। इसलिए राहत शिविर में भोजन उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। बाढ़ के बाद परिवारों की आर्थिक पुनर्बहाली की योजना भी उतनी ही जरूरी है।

शहरों की जल निकासी पर गंभीर सवाल

बारिश के दौरान सबसे अधिक चर्चा महानगरों और बड़े शहरों के जलभराव की होती है। हर वर्ष करोड़ों रुपये नालों की सफाई, सड़क सुधार और जल निकासी पर खर्च किए जाते हैं। फिर भी पहली तेज बारिश में ही कई प्रमुख सड़कें तालाब बन जाती हैं। इसका कारण केवल नालों की सफाई नहीं है, बल्कि शहरी जल निकासी व्यवस्था को पूरे जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखना होगा। यदि किसी क्षेत्र में बारिश का पानी तेजी से आता है और निकासी क्षमता उससे कम है, तो सड़क और नाले दोनों अपनी सीमा पर पहुंच जाएंगे। शहरी नियोजन में पुराने तालाबों, झीलों, नालों और प्राकृतिक जलमार्गों को बचाना इसलिए जरूरी है। इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि शहरी सुरक्षा का प्रश्न है।

नदियों के साथ खिलवाड़ का परिणाम

नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं हैं। उनका अपना प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र होता है। बाढ़ के समय नदी अपने फैलाव क्षेत्र में पानी छोड़ती है। जब मनुष्य उस क्षेत्र में स्थायी निर्माण कर देता है तो टकराव अपरिहार्य हो जाता है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच कृत्रिम संघर्ष पैदा करने के बजाय वैज्ञानिक संतुलन बनाना होगा। नदी किनारे निर्माण की अनुमति देने से पहले बाढ़ के पुराने आंकड़ों, जलस्तर, प्रवाह और भविष्य के जलवायु जोखिमों का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। नदियों के प्राकृतिक मार्ग को संकुचित करके हम थोड़े समय के लिए जमीन तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपदा का जोखिम बढ़ाते हैं।

मौसम चेतावनी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा

आज मौसम विज्ञान पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम है। उपग्रह, रडार और आधुनिक पूर्वानुमान प्रणालियां संभावित भारी बारिश की जानकारी पहले उपलब्ध करा देती हैं। लेकिन चेतावनी का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह समय पर नागरिक तक पहुंचे। एक किसान के लिए मौसम विभाग की तकनीकी भाषा हमेशा उपयोगी नहीं होती। उसे सरल शब्दों में यह जानना जरूरी है कि अगले 24 घंटे में क्या खतरा है, खेत से पानी कैसे निकाला जाए, पशुओं को कहां रखा जाए और सुरक्षित स्थान कौन सा है। इसी तरह शहरों में नागरिकों को केवल भारी बारिश का अलर्ट नहीं, बल्कि जलभराव वाले मार्गों, यातायात प्रतिबंधों, सुरक्षित आश्रय स्थलों और आपातकालीन नंबरों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। पूर्व चेतावनी तभी प्रभावी है जब वह पूर्व कार्रवाई में बदल जाए।

राहत व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल

बाढ़ प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाना होगा। ड्रोन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, उपग्रह तस्वीरों से जलभराव की पहचान, मोबाइल आधारित चेतावनी और वास्तविक समय में नदी के जलस्तर की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। जिला प्रशासन के पास यह स्पष्ट डिजिटल मानचित्र होना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति में कौन-से गांव पहले प्रभावित हो सकते हैं, किन मार्गों से निकासी होगी, कहां राहत शिविर बनाए जाएंगे और किन स्थानों पर चिकित्सा दल तैनात किए जाएंगे। आपदा के समय निर्णय लेने में देरी कई बार नुकसान को कई गुना बढ़ा देती है।

किसान को केवल मुआवजा नहीं, सुरक्षा चाहिए

हर बाढ़ के बाद किसानों को मुआवजे की घोषणा होती है। यह जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कृषि नीति में बाढ़-सहिष्णु फसलों, फसल बीमा की प्रभावी पहुंच, स्थानीय जल प्रबंधन और मौसम आधारित कृषि सलाह को मजबूत करना होगा। यदि किसान को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा के बाद फिर से शुरुआत करनी पड़े तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक कृषि योजना बननी चाहिए। जहां बार-बार बाढ़ आती है, वहां फसल चयन और खेती के तरीके भी उसी के अनुरूप होने चाहिए।

जल संकट और बाढ़ का विरोधाभास

विचित्र है—बारिश के मौसम में पानी से संकट और गर्मियों में पानी की कमी। इस विरोधाभास का समाधान वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन में छिपा है। शहरों में वर्षा जल संचयन, गांवों में तालाबों का पुनर्जीवन, छोटे जलाशयों का निर्माण और भूजल पुनर्भरण को व्यापक अभियान बनाना होगा। यदि भारी बारिश का पानी सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके तो बाढ़ का दबाव भी कम होगा और गर्मियों में जल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी।

आपदा प्रबंधन को चुनावी घोषणा नहीं, स्थायी नीति बनाएं

बाढ़ के समय राजनीतिक बयान तेजी से आते हैं। निरीक्षण होते हैं, राहत पैकेज घोषित होते हैं और तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन असली काम तब शुरू होना चाहिए जब पानी उतर जाए। बाढ़ समाप्त होने के बाद यह वैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए कि पानी कहां से आया, कौन-से बांध या तटबंध कमजोर पड़े, कौन-से नाले अवरुद्ध थे, कौन-से गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए और अगली बार नुकसान कैसे कम किया जा सकता है। हर बड़ी बाढ़ के बाद ऐसी सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक होनी चाहिए। गलतियों से सीखना ही बेहतर आपदा प्रबंधन की पहली शर्त है।

केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी

नदियां राज्य की सीमाओं का पालन नहीं करतीं। एक राज्य में भारी बारिश का प्रभाव दूसरे राज्य में नदी के जलस्तर के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए बाढ़ प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के बीच वास्तविक समय पर सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जलाशयों से पानी छोड़ने, नदी जलस्तर, मौसम पूर्वानुमान और निकासी योजनाओं की जानकारी समय पर साझा होने से कई जानें बचाई जा सकती हैं।

अब राहत नहीं, जोखिम घटाने की नीति चाहिए

देश को अब यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसी स्थिति में पुरानी व्यवस्थाओं के भरोसे भविष्य की आपदाओं का सामना नहीं किया जा सकता। सड़कें चौड़ी करने से अधिक जरूरी है कि उनके साथ जल निकासी की क्षमता बढ़ाई जाए। नई कॉलोनियां बसाने से पहले बाढ़ और जलभराव का जोखिम देखा जाए। नदी किनारे विकास की अनुमति वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर दी जाए। पुराने जलाशयों और प्राकृतिक जलमार्गों को संरक्षित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात—आपदा प्रबंधन का केंद्र इमारतें नहीं, इंसान होने चाहिए। किसी भी विकास योजना की सफलता का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि संकट की घड़ी में वह नागरिकों की कितनी रक्षा कर सकती है।

निष्कर्ष: बारिश से नहीं, तैयारी की कमी से हारना बंद करे भारत

में मानसून जीवनदायी है। यही वर्षा खेतों को पानी देती है, जलाशयों को भरती है और अर्थव्यवस्था को गति देती है। समस्या बारिश नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन की कमजोरी है। आज जब देश के अनेक हिस्से भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, तब यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, आत्ममंथन का है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें मौसम की चेतावनी के बाद प्रशासन सक्रिय हो, नदी के बढ़ते जलस्तर के साथ निकासी योजना शुरू हो, किसानों तक समय पर सलाह पहुंचे और शहरों में जल निकासी पहले से तैयार रहे। प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा का नुकसान कम किया जा सकता है। भारत को अब हर वर्ष बाढ़ के बाद यह पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इतना पानी क्यों भर गया? बल्कि पहले से यह तय होना चाहिए कि यदि इतना पानी आएगा तो हम उसकी सुरक्षित निकासी कैसे करेंगे? यही सोच भारत को राहत-आधारित व्यवस्था से निकालकर जोखिम-आधारित आपदा प्रबंधन की ओर ले जाएगी। और यही समय की सबसे बड़ी मांग है।

अंतरिक्ष से धरती तक नई नजर

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

भारत की अंतरिक्ष यात्रा को यदि केवल रॉकेटों की उड़ान और उपग्रहों की संख्या के आधार पर देखा जाए, तो उसकी वास्तविक कहानी अधूरी रह जाएगी। अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी सफलता तब होती है, जब आकाश में स्थापित तकनीक धरती पर रहने वाले सामान्य नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक बने। मौसम की सटीक जानकारी हो, बाढ़ और चक्रवात की निगरानी हो, कृषि योजनाओं का निर्माण हो, जंगलों और जल संसाधनों का अध्ययन हो अथवा प्राकृतिक आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता—आज अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़े आधुनिक शासन और विकास व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनते जा रहे हैं। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का आगामी GSLV-F17/EOS-05 मिशन विशेष महत्व रखता है। इसरो के अनुसार, मिशन का प्रक्षेपण 4 सितंबर 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह 2:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण परिसर से निर्धारित है। GSLV-F17, भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 19वीं उड़ान होगी और इसे EOS-05 को सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इस मिशन का महत्व केवल एक निर्धारित प्रक्षेपण तक सीमित नहीं है। यह भारत की पृथ्वी-अवलोकन क्षमता के विकास में एक नए अध्याय की शुरूआत का संकेत देता है। जब अंतरिक्ष की नजर धरती के काम आए EOS-05 को इसरो ने अत्याधुनिक पृथ्वी-अवलोकन अंतरिक्षयान बताया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत का जियोसिंक्रोनस कक्षा से पृथ्वी की इमेजिंग करने वाला पहला उपग्रह होगा। यह तकनीकी उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की निगरानी केवल तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका संबंध समय पर सूचना, बेहतर विश्लेषण और अधिक प्रभावी निर्णयों से होता है। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में मौसम और पर्यावरण की परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हो सकता है, मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर आ सकती हैं, समुद्री तटों पर चक्रवात की चुनौती उत्पन्न हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति विकसित हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में समय पर और विश्वसनीय जानकारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। यहीं से अंतरिक्ष तकनीक का वास्तविक महत्व शुरू होता है। एक उपग्रह अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन उससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग अंततः धरती पर ही होता है। किसी नदी के फैलाव का आकलन करना हो, बादलों की गतिविधि को समझना हो, पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन करना हो अथवा बड़े भूभाग में परिवर्तन की निगरानी करनी हो—अंतरिक्ष आधारित अवलोकन प्रणालियां प्रशासन और वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए उपयोगी साधन बन सकती हैं। इस अर्थ मे EOS-05 केवल एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं, बल्कि भविष्य की सूचना-आधारित निर्णय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। आपदा प्रबंधन में समय ही सबसे बड़ी पूंजी भारत हर वर्ष अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा और सूखे जैसी परिस्थितियां केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं रहतीं; इनका सीधा असर लोगों के जीवन, कृषि, सड़क और रेल नेटवर्क, बिजली व्यवस्था तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है—स्थिति की जानकारी कितनी जल्दी और कितनी स्पष्टता से मिलती है? यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, तो प्रशासन को प्रभावित इलाकों का आकलन शीघ्रता से करना होता है। यदि किसी समुद्री क्षेत्र में चक्रवात विकसित हो रहा है, तो समय रहते चेतावनी और तैयारी आवश्यक होती है। यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा हो रही है, तो सड़क और बस्तियों की सुरक्षा पर तुरंत ध्यान देना पड़ सकता है। ऐसे समय में जमीन से प्राप्त जानकारी और अंतरिक्ष आधारित अवलोकन एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि कोई एक उपग्रह सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को मौसम विज्ञान, भूगर्भीय अध्ययन, जमीनी सर्वेक्षण, प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय चेतावनी प्रणाली के साथ जोड़ना पड़ता है। तकनीक तभी प्रभावी होती है, जब उसके आधार पर समय पर और सही निर्णय लिए जाएं। इसलिए EOS-05 जैसे मिशन की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन केवल सफल प्रक्षेपण से नहीं, बल्कि भविष्य में उससे मिलने वाली उपयोगी सेवाओं और उनके सामाजिक प्रभाव से किया जाना चाहिए। जियोसिंक्रोनस इमेजिंग की नई दिशा पारंपरिक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों और जियोसिंक्रोनस कक्षा से इमेजिंग की अवधारणा में अंतर को समझना भी आवश्यक है। पृथ्वी की निगरानी करने वाले अलग-अलग उपग्रह विभिन्न कक्षाओं और उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते हैं। जियोसिंक्रोनस कक्षा से किसी बड़े क्षेत्र को बार-बार देखने की क्षमता भारत के लिए पृथ्वी-अवलोकन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकती है। इसरो के अनुसार EOS-05 भारत का पहला ऐसा इमेजिंग उपग्रह होगा, जो जियोसिंक्रोनस कक्षा से पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसका उद्देश्य भारत की पृथ्वी-अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करना और संबंधित सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अंतरिक्ष विज्ञान में हर नई क्षमता केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होती। उसके साथ डेटा प्रबंधन, वैज्ञानिक विश्लेषण, संस्थागत समन्वय और आम उपयोगकर्ताओं तक सेवाओं की पहुंच की चुनौती भी जुड़ी होती है। उपग्रह जितना उन्नत होगा, उतना ही आवश्यक होगा कि उससे मिलने वाली जानकारी को समझने और उपयोग में लाने की व्यवस्था भी मजबूत हो। कृषि और जल संसाधनों के लिए संभावनाएं भारत की बड़ी आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मौसम की अनिश्चितता और बदलती जलवायु परिस्थितियां खेती के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। किस क्षेत्र में वर्षा की स्थिति कैसी है, भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन हो रहा है, जल संसाधनों की स्थिति क्या है और पर्यावरण में दीर्घकालिक बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं—ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने में पृथ्वी-अवलोकन तकनीक की भूमिका बढ़ती जा रही है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े अपने आप में अंतिम समाधान नहीं होते, लेकिन वे वैज्ञानिक और प्रशासनिक निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों को जमीनी आंकड़ों और स्थानीय विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाए, तो कृषि योजना, जल प्रबंधन और प्राकृतिक

संसाधनों की निगरानी अधिक वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है। यही वह दिशा है जिसमें भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को आम जनजीवन से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। GSLV-F17: केवल प्रक्षेपण यान नहीं EOS-05 मिशन की चर्चा उपग्रह तक सीमित नहीं रह सकती। उसे अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपण यान की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। GSLV-F17 भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम की 19वीं उड़ान है। इसरो ने इसे चार मीटर व्यास वाले ओजाइव कंपोजिट पेलोड फेयरिंग विन्यास के साथ तैयार किए गए मिशन के रूप में सूचीबद्ध किया है। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सेकंड लॉन्च पैड से होना निर्धारित है। किसी अंतरिक्ष मिशन की सफलता अनेक चरणों पर निर्भर करती है। प्रक्षेपण यान की तकनीकी विश्वसनीयता, उपग्रह का प्रदर्शन, कक्षा में स्थापित होने की प्रक्रिया और उसके बाद दीर्घकालिक संचालन—हर चरण महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 4 सितंबर की सुबह केवल एडर-05 की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उस वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था की भी परीक्षा होगी जिसने वर्षों की मेहनत से इस मिशन को प्रक्षेपण तक पहुंचाया है। अंतरिक्ष विज्ञान में असफलता भी एक पाठ है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सफलता की सीधी और आसान कहानी नहीं रहा है। हर वैज्ञानिक यात्रा की तरह इसमें भी चुनौतियां, विलंब और कुछ असफल मिशन रहे हैं। GSLV के इतिहास में भी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसरो के आधिकारिक रिकॉर्ड में GSLV-F10/EOS-03 मिशन को 2021 में असफल बताया गया था। ऐसे अनुभव अंतरिक्ष विज्ञान की कठिन प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन विज्ञान की असली शक्ति यही है कि वह असफलता को अंतिम परिणाम नहीं मानता। हर तकनीकी चुनौती के बाद कारणों की जांच होती है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। प्रणालियों में सुधार किए जाते हैं और फिर अगला प्रयास अधिक तैयारी के साथ किया जाता है। किसी अंतरिक्ष एजेंसी की परिपक्वता का मूल्यांकन केवल उसकी सफल उड़ानों से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि वह कठिन परिस्थितियों से क्या सीखती है। EOS-05 मिशन इसी व्यापक वैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा है। सात महीने बाद एक महत्वपूर्ण उड़ान इस मिशन का महत्व इसरो की 2026 की प्रक्षेपण गतिविधियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हाल के महीनों के अंतराल के बाद यह मिशन अंतरिक्ष एजेंसी की प्रक्षेपण गतिविधियों में महत्वपूर्ण वापसी के रूप में सामने आया है। इससे यह संदेश भी मिलता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लगातार प्रक्षेपणों की दौड़ नहीं है। कभी-कभी तकनीकी समीक्षा, परीक्षण, विश्लेषण और तैयारी के लिए समय देना भी उतना ही आवश्यक होता है। अंतरिक्ष विज्ञान में जल्दबाजी की तुलना में विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के लिए आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहने वाला है। निजी कंपनियों की भागीदारी, स्टार्टअप, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान इस क्षेत्र को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे समय में इसरो की प्रत्येक महत्वपूर्ण उड़ान देश की समग्र अंतरिक्ष क्षमता के लिए एक आधार तैयार करती है। अंतरिक्ष और राष्ट्रीय विकास का नया संबंध कभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैज्ञानिक गौरव से जोड़कर देखा जाता था। वह दृष्टिकोण आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज अंतरिक्ष तकनीक का संबंध संचार, नेविगेशन, मौसम, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों से है। इसलिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि अंतरिक्ष में निवेश का सामाजिक और आर्थिक लाभ कितना व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचता है। यदि उपग्रह से प्राप्त आंकड़े केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित रह जाएं, तो उनकी क्षमता अधूरी रह जाएगी। लेकिन यदि यही जानकारी किसी किसान तक बेहतर सलाह के रूप में पहुंचे, किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य को तेज करे, किसी राज्य को जल संसाधन प्रबंधन में सहायता दे या किसी शहर को पर्यावरणीय योजना बनाने में मदद करे, तभी अंतरिक्ष तकनीक का वास्तविक लोकतंत्रीकरण होगा। भारत को अब इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। डेटा होगा, तो जिम्मेदारी भी होगी एडर-05 जैसे मिशनों के साथ एक नई चुनौती डेटा के उपयोग और प्रबंधन की भी है। अधिक जानकारी का अर्थ हमेशा बेहतर निर्णय नहीं होता। जानकारी को सही तरीके से पढ़ना, उसकी सीमाओं को समझना और उसे विश्वसनीय जमीनी आंकड़ों के साथ मिलाना आवश्यक है। भविष्य में भारत के सामने केवल उपग्रह बनाने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करने की भी आवश्यकता होगी। डेटा वैज्ञानिक, मौसम विशेषज्ञ, भूगोलवेत्ता, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी—सभी को आधुनिक अंतरिक्ष आधारित जानकारी का प्रभावी उपयोग सीखना होगा। अंतरिक्ष तकनीक तभी उपयोगी होगी, जब उसके और धरती पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं के बीच मजबूत सेतु बनेगा। सुबह 2:55 बजे केवल एक रॉकेट नहीं उड़ेगा 4 सितंबर की सुबह 2:55 बजे जब श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के उड़ान भरने का निर्धारित समय आएगा, तब देश की निगाहें स्वाभाविक रूप से इसरो के मिशन पर होंगी। इसरो ने मिशन के लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की है। लेकिन उस क्षण को केवल एक रॉकेट लॉन्च के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। वह भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और व्यावहारिक विकास आवश्यकताओं के मिलन का क्षण भी होगा। रॉकेट का लक्ष्य अंतरिक्ष है, लेकिन उसका उद्देश्य धरती से जुड़ा हुआ है। विज्ञान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है—मनुष्य अपनी नजर आकाश तक पहुंचाता है, ताकि वह अपनी धरती को अधिक अच्छी तरह समझ सके। सफलता की असली कसौटी क्या होगी? EOS-05 मिशन की सफलता की पहली कसौटी निश्चित रूप से सुरक्षित और सफल प्रक्षेपण होगी। इसके बाद उपग्रह को निर्धारित कक्षा और परिचालन क्षमता तक पहुंचना होगा। लेकिन संपादकीय दृष्टि से इसकी सबसे बड़ी कसौटी इससे भी आगे है। क्या यह मिशन भारत की पृथ्वी-अवलोकन क्षमता को वास्तव में मजबूत करेगा? क्या इससे मिलने वाले आंकड़े आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होंगे? क्या इन सेवाओं का लाभ राज्यों, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा? क्या भारत अंतरिक्ष से प्राप्त विशाल डेटा को समयबद्ध और प्रभावी निर्णयों में बदल पाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले वर्षों में मिलेंगे। अंतरिक्ष की उपलब्धि, धरती की जिम्मेदारी भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान के उस चरण में पहुंच चुका है, जहां उसे केवल नई ऊंचाइयों को छूने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब चुनौती यह है कि अंतरिक्ष से मिलने वाली शक्ति को धरती पर बेहतर जीवन में कैसे बदला जाए। EOS-05 मिशन इसी परिवर्तनशील सोच का प्रतीक है। भारत के लिए अंतरिक्ष अब केवल गौरव का विषय नहीं है। यह विकास की योजना बनाने, प्राकृतिक संसाधनों को समझने, आपदाओं से निपटने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। फिर भी, वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर उत्साह के साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण भी आवश्यक है। एक उपग्रह से सभी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। तकनीक के साथ मजबूत संस्थाएं, प्रशिक्षित मानव संसाधन, जमीनी व्यवस्था और प्रभावी प्रशासन भी चाहिए। अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी तभी सार्थक होगी, जब वह सही समय पर सही व्यक्ति और सही निर्णय तक पहुंचे। नई उड़ान, नई जिम्मेदारी श्रीहरिकोटा से होने वाला GSLV-F17/EOS-05 प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसरो के अनुसार यह भारत का पहला जियोसिंक्रोनस कक्षा से पृथ्वी की इमेजिंग करने वाला उपग्रह होगा और इससे देश की पृथ्वी-अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में नई संभावना जुड़ेगी। देश को इस मिशन से वैज्ञानिक सफलता की उम्मीद है, लेकिन उससे भी बड़ी उम्मीद यह है कि भारत की अंतरिक्ष क्षमता भविष्य में आम नागरिकों की सुरक्षा, विकास और बेहतर जीवन के लिए अधिक प्रभावी रूप से उपयोग की जाएगी। 4 सितंबर की सुबह जब GSLV-F17 आकाश की ओर बढ़ेगा, तो उसके साथ केवल EOS-05 ही नहीं जाएगा। उसके साथ भारत की एक नई सोच भी आगे बढ़ेगी—अंतरिक्ष को जीतने की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की शक्ति से धरती को बेहतर समझने और संवारने की सोच। यही किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है और शायद यही EOS-05 मिशन का सबसे व्यापक अर्थ भी।

बारूद के साये में दुनिया: ईरान संकट से फिर परीक्षा में वैश्विक कूटनीति

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां युद्ध की आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसका धुआं पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय व्यवस्था को प्रभावित करने लगता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के फिर तेज होने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है—क्या दुनिया कूटनीति के माध्यम से संकट को नियंत्रित कर पाएगी या सैन्य टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेगा? ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके बाद ईरान की जवाबी मिसाइल एवं ड्रोन कार्रवाइयों ने तनाव को फिर बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों पर हमलों की निंदा करते हुए तत्काल शत्रुता रोकने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार संघर्ष में बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की खबरें सामने आई हैं। यह केवल अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं है। इसके प्रभाव की परिधि पश्चिम एशिया से निकलकर विश्व ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार, महंगाई और वैश्विक कूटनीति तक पहुंच सकती है। युद्ध का सबसे बड़ा खतरा नागरिकों के लिए किसी भी युद्ध का पहला और सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। सैन्य रणनीति और राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन परिवारों की आवाज अक्सर दब जाती है, जिनके घर उजड़ते हैं, बच्चे घायल होते हैं और रोजमर्रा का जीवन भय में बदल जाता है। अमेरिका-ईरान संघर्ष के ताजा दौर में भी नागरिक हताहतों की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ाई है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी हमलों में लोगों की मौत और बड़ी संख्या में घायल होने की घटनाएं हुई हैं, जबकि ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए गए हैं। युद्ध में किसी एक पक्ष की सैन्य क्षमता की चर्चा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह प्रश्न भी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और नागरिकों की सुरक्षा का पालन किस हद तक हो रहा है। यही वह कसौटी है जिस पर बड़ी शक्तियों सहित सभी पक्षों को परखा जाना चाहिए। होमुर्ज: दुनिया की ऊर्जा नस पर दबाव इस संकट की सबसे गंभीर आर्थिक परत होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होती है या जोखिम बढ़ता है, तो कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति पर तत्काल असर पड़ सकता है। ताजा रिपोर्टों में ईरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण के दावे और अमेरिका की अलग स्थिति का उल्लेख है। इस टकराव के बीच तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। भारत सहित एशिया के अनेक देश ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। इसलिए पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सीधे तौर पर पेट्रोलियम कीमतों, परिवहन लागत और अंततः आम उपभोक्ता की जेब को प्रभावित कर सकता है। यदि तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। विमानन से लेकर परिवहन और उद्योग तक, ऊर्जा लागत में वृद्धि का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों तक पहुंचता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को युद्ध से क्यों डरना चाहिए? आज की विश्व अर्थव्यवस्था आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक क्षेत्र का संकट दूसरे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। तेल महंगा होने पर आयातक देशों का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ऊर्जा लागत बढ़ने पर उत्पादन महंगा हो सकता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा होता है। दूसरी ओर, यदि केंद्रीय बैंक महंगाई नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को ऊंचा रखते हैं, तो निवेश और आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए पश्चिम एशिया का सैन्य संकट केवल विदेश नीति का विषय नहीं है। यह आर्थिक नीति का भी विषय है। भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा और घरेलू उत्पादन की क्षमता का महत्व ऐसे समय में और बढ़ जाता है। कूटनीति की परीक्षा इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दुनिया ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक युद्धों और संघर्षों से यह सबक लिया है कि सैन्य समाधान अक्सर स्थायी शांति नहीं दे पाते। फिर भी बातचीत की मेज तक पहुंचने से पहले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र की अपीलें तभी प्रभावी होंगी, जब संबंधित शक्तियां उन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति से समर्थन दें। केवल बयान जारी करना पर्याप्त नहीं है। संकट को रोकने के लिए प्रत्यक्ष संवाद, मध्यस्थता और चरणबद्ध तनाव-नियंत्रण की आवश्यकता है। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास पुराना है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने दोनों देशों के संबंधों को लंबे समय से तनावपूर्ण बनाए रखा है। लेकिन स्थायी समाधान का रास्ता सैन्य शक्ति से अधिक राजनीतिक समझौते से होकर जाता है। क्या दुनिया फिर दो खेमों में बंट रही है? यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक राजनीति में पहले ही गहरे ध्रुवीकरण की स्थिति बन चुकी है। अब पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष इस विभाजन को और गहरा कर सकता है। रूस, चीन, यूरोप और अमेरिका की पश्चिम एशिया संबंधी प्राथमिकताएं पूरी तरह समान नहीं हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का प्रभाव वैश्विक शक्ति-संतुलन पर पड़ सकता है। दुनिया को इस समय किसी नए शीतयुद्ध की नहीं, बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियां किसी एक देश की सीमा में नहीं रुकतीं। यदि बड़ी शक्तियां अपने रणनीतिक हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करती हैं, तो इसका दीर्घकालीन नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। गाजा और यूक्रेन भी चेतावनी हैं पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट उस व्यापक अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से अलग नहीं है, जिसमें गाजा और यूक्रेन जैसे संघर्ष लगातार मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं। गाजा में युद्ध की परिस्थितियों के बीच कृषि व्यवस्था और स्थानीय खाद्य सुरक्षा तक प्रभावित हुई है। यूक्रेन में भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहने से नागरिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इन सभी संघर्षों में एक समान बात दिखाई देती है—सैन्य कार्रवाई शुरू करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन शांति स्थापित करना अत्यंत कठिन। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संघर्षों को रोकने के लिए युद्ध शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि तनाव बढ़ने के शुरूआती चरण में ही सक्रिय होना चाहिए। भारत के लिए क्या संदेश? भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय हित और सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद पर आधारित रही है। वर्तमान पश्चिम एशियाई संकट में भी भारत के लिए संतुलित कूटनीति महत्वपूर्ण है। भारत के पश्चिम एशिया के देशों के साथ गहरे आर्थिक और मानवीय संबंध हैं। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में काम करते हैं। ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा भारत के प्रत्यक्ष हितों से जुड़े मुद्दे हैं। ऐसे समय में भारत को एक ओर अपने नागरिकों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, तो दूसरी ओर सभी संबंधित पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। भारत की भूमिका किसी पक्ष का समर्थन करने से अधिक शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की वकालत करने में प्रभावी हो सकती है। युद्ध की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं इतिहास बताता है कि युद्ध का वास्तविक मूल्य केवल हथियारों और सैन्य बजट में नहीं मापा जाता। युद्ध स्कूलों को बंद करता है, अस्पतालों को दबाव में डालता है, परिवारों को विस्थापित करता है और अर्थव्यवस्थाओं को वर्षों पीछे धकेल सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि युद्ध की पीढ़ीगत स्मृति आने वाले दशकों तक समाजों में अविश्वास और कटुता पैदा करती है। इसलिए आज दुनिया के सामने चुनौती केवल यह नहीं है कि कौन सैन्य रूप से अधिक शक्तिशाली है। वास्तविक चुनौती यह है कि कौन राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व है कि शक्ति का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में करे। अब निर्णय का समय है पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट विश्व समुदाय के लिए एक और चेतावनी है। यदि संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा।

पुस्तक समीक्षा - प्रेम कलश खण्डकाव्य

प्रेम कलश पुस्तक आजमगढ़ जनपद के प्रतिष्ठित कवि श्री रुद्रनाथ चौबे 'रुद्र' जी द्वारा रचित श्रृंगार रस से ओतप्रोत, मनमुग्ध कर देने वाला मनोहारी खण्डकाव्य है। जो कि 'कामायनी प्रकाशन' प्रयागराज से प्रकाशित है। खण्डकाव्य प्रेम कलश की विधिवत भूमिका श्रीराम तिवारी 'सहज' जी ने लिखी है, यह बड़े गौरव की बात है। पुस्तक के शीर्षक से ही हमें यह आभास होने लगता है कि यह पुस्तक पूर्ण रूप से श्रृंगारिक रचना होगी और ऐसा है भी। प्रश्न उठता है कि कवि रुद्रनाथ 'रुद्र' जी ने सिर्फ. प्रेम और कलश को ही क्यों चुना? विषय तो और भी हो सकते थे। तो इसका एकमात्र उत्तर यही है कि कवि के मन में आदर्श और आध्यात्मिक प्रेम की अगाध भावना समाहित है। जिसके परिणामस्वरूप श्री 'रुद्र' जी ने अपनी लेखनी को प्रेम से अभिसिंचित करके प्रेम कलश जैसा मनोहारी खण्डकाव्य की रचना की। जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। कुल पाँच खण्डों में विभक्त खण्डकाव्य, प्रेम की व्यापकता से लबरेज है। इस खण्डकाव्य में कुल एक सौ छत्तीस पद हैं। अधिकांश पदों में प्रेम रूपी शब्द विद्यमान है। खण्डकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम पद ही संपूर्ण पुस्तक की व्याख्या करने का भाव लिए परिलक्षित होता है। जो निम्न है - प्रेम कलश की प्रेम भित्ति पर, प्रेम चिन्ह अंकित था। स्वास्तिक वंदनवारों से वह, पूरी तरह अलंकृत था।। कविवर श्री 'रुद्र' जी ने प्रतीकों के माध्यम से प्रेम रस के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होकर पावन कलश की स्थापना को मूर्त रूप देने का सार्थक प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्हें भरपूर सफलता भी अर्जित हुई है। वह भी ऐसा कलश जो एक मिट्टी का बना पात्र नहीं, बल्कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्माण्ड को एक कलश के रूप में स्वीकारा है। कलश शीतलता का प्रतीक है, सुख-समृद्धि का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। जब इसी स्थूल कलश में प्रकृति और पुरुष का प्रेमालाप होगा तो निश्चित ही मानव मन अभिरंजित होगा। कविवर श्री 'रुद्र' जी ने शिव और शिवा जैसी दैवीय शक्तियों का मानवीकरण करते हुए प्रेम कलश खण्डकाव्य को और भी ऊँचाई प्रदान की है। प्रेम ही ईश्वर है इस कथन की व्यापकता प्रेम कलश में विस्तृत रूप में विद्यमान है। प्रेम अचानक नहीं होता। जिस प्रकार मिट्टी के अंदर छिपे बीज का एक परिपक्व वृक्ष बन

जाने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती। एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। एक लंबा समय लगता है। इस लंबे समय के एक-एक सोपान में उस बीज की जीवन-गाथा समाई होती है। उसी प्रकार सुकवि श्री 'रुद्र' जी ने प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव का बखूबी वर्णन किया है। जिसमें अनेकों रसों का समावेश है। वे रस हमारे मन को हर समय आंदोलित करते रहते हैं। कविवर श्री 'रुद्र' जी ने शिव और शिवा के अलावा प्रकृति से जुड़े अनेक गौरवपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। कलश और उसमें परिपूर्ण जल की पवित्रता पर अपनी सशक्त लेखनी का परिचय देते हुए कवि 'रुद्र' जी लिखते हैं - नीर भरा था प्रेम कलश में, फूलों के मकरंद घुले। आनंद सुगंध सुवासित जल में, प्रेम शक्ति के छंद मिले।। श्री रुद्रनाथ 'रुद्र' जी द्वारा रचित खण्डकाव्य प्रेम कलश के पाँचों सर्ग, श्रृंगार रस के विभिन्न बिंदुओं से होकर प्रवाहित होते हैं। प्रथम सर्ग में कवि ने प्रेम कलश व दो काल्पनिक पात्र शिव और शिवा का विधिवत परिचय कराया है। जोकि नितांत आवश्यक था। द्वितीय सर्ग में कवि ने प्रेम कलश रूपी संसार में शिव और शिवा नामक नायक व नायिका के सूक्ष्म मिलन का बड़ा ही रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। जब दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा, तथा नायक और नायिका एक-दूसरे को पसंद करने लगे। इसी प्रकार तृतीय सर्ग में कविवर 'रुद्र' जी ने नायक और नायिका के बीच पनपे प्रेमांकुर को और प्रगाढ़ता की तरफ पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए 'रुद्र' जी लिखते हैं - नई नवेली नूतन सी नायिका, बन सज के शिवा सँवरी थी। मानो रति श्रृंगार सजाकर, आज अवनि पर उतरी थी।। चतुर्थ सर्ग में कवि ने नायक-नायिका के वियोग का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। जो पाठकों के दिलों को आंदोलित करता है, तथा इसी सर्ग में अंकित कई पद हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आने पर एक संबल प्रदान करने में सहायक भी हो सकते हैं। उसकी एक बानगी देखें - तन से दूर भले जाऊँ पर, मन तेरे साथ रहेगा। पल-पल चिंतन होगा, तन आस लिए तड़पेगा।। पंचम सर्ग जो 'प्रेम कलश' का अंतिम सर्ग है, जिसमें कविवर 'रुद्र' जी ने वियोग व वियोग के लंबे अंतराल के बाद नायक और नायिका का मिलन बड़े ही सराहनीय ढंग से दर्शाया है। इसी प्रेम कलश में शिवा और शिव जो कि इस खण्डकाव्य के काल्पनिक पात्र हैं, वे संसार रूपी कलश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार खण्डकाव्य पूर्ण हो जाता है। अर्थात कविवर 'रुद्र' जी के हृदय में समग्र संसार को देखने, समझने व वर्णन करने का जो नजरिया है, वह बिल्कुल सहज है। जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण जगत को राममय मानते हुए कहा है - सियाराम मय सब जग जानी, करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी।। उसी प्रकार 'रुद्र' जी ने संपूर्ण जगत में यदि कहीं भी अपनी दृष्टि डाली है तो उन्हें सिर्फ प्रेम का दर्शन और प्रेम का ही आभास हुआ है, जो कि समाज और साहित्य के लिए बड़े गौरव की बात है। हालाँकि कविवर 'रुद्र' जी ने यह बताने में कुछ कोताही अवश्य की है कि नायक और नायिका का वियोग किस कारणवश हुआ। कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ आईं, जब शिव और शिवा अलगाव की स्थिति में जा पहुँचे। कौन-सी परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि जब उनका पुनर्मिलन हुआ। फिर भी सब मिलाकर यह रससिक्त खंड काव्य मनोहारी है। अतः मैं लालबहादुर चौरसिया 'लाल' कविवर 'रुद्र' जी को उनकी इस प्रेम रस से अभिसिंचित पुस्तक की सर्जना के लिए बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह प्रेम कलश खण्डकाव्य साहित्य जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। कविवर डॉ रुद्रनाथ चौबे 'रुद्र' जी को अनंत शुभकामनाएँ...

-लालबहादुर चौरसिया 'लाल'
साहित्यकार एवं कवि महामंत्री - विश्व हिंदी शोध एवं संवर्धन अकादमी आजमगढ़ इकाई
9452088890

समीक्षक - लालबहादुर चौरसिया 'लाल'
साहित्यकार एवं कवि
महामंत्री - विश्व हिंदी शोध एवं
संवर्धन अकादमी आजमगढ़ इकाई

सूखे पर विशेष सत्र बुलाए सरकार : विजयेंद्र

5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने और नवली समानांतर जलाशय को प्राथमिकता देने की मांग

भारतार्थ खबर
Bhaaarataarth.com

गुडादुर, 3 सितंबर 2026। कर्नाटक में सूखे और किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति, किसानों की आत्महत्याओं और कृषि संकट से जुड़ी समस्याओं पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विजयेंद्र ने सूखा प्रभावित किसानों के 5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की मांग भी सरकार के सामने रखी। बेल्लारी चलो पदयात्रा के तीसरे दिन गुडादुर से यात्रा शुरू होने के बाद मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों की मौजूदा स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पांच गारंटी योजनाओं को ही विकास का पर्याय मानकर चल रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आर्थिक और मौसम संबंधी संकट से जूझ रहे हैं। 190 से अधिक तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग विजयेंद्र ने राज्य के 190 से अधिक तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सूखे की गंभीरता को देखते हुए किसानों को तत्काल राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कृषि ऋण माफी के साथ सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। विजयेंद्र ने नवली समानांतर जलाशय परियोजना को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में सिंचाई और जल उपलब्धता की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। जलाशयों के मुद्दे को उठाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तुंगभद्रा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि होसपेट बांध में बड़ी मात्रा में गाद जमा होने से उसकी जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल में नवली समानांतर जलाशय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की दिशा में धन उपलब्ध कराया गया था। विजयेंद्र ने सरकार से इस परियोजना को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के किसानों के लिए दीर्घकालिक सिंचाई समाधान तैयार करने की मांग की। डी.के. शिवकुमार पर भी साधा निशाना विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर किसानों की समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की वास्तविक परेशानियों को समझने के लिए सरकार को उनके बीच जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूखे जैसी गंभीर परिस्थिति में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को अपना अधिक समय किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए देना चाहिए। हालांकि, मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर लगाए गए इन राजनीतिक आरोपों पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का उल्लेख इस वक्तव्य में नहीं है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों का किया उल्लेख विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कर्नाटक में करीब 3,655 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 937, कलबुर्गी में करीब 294, रायचूर में 160 से अधिक, बीदर में 220 से अधिक और कोप्पल में 80 से अधिक किसानों की आत्महत्या का दावा किया। इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि और अवधि के संदर्भ को संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से देखना आवश्यक है। विजयेंद्र ने इन आंकड़ों का उल्लेख करते हुए सरकार से किसान संकट पर तत्काल गंभीर कदम उठाने की मांग की। ज्वार उत्पादकों के भुगतान का मुद्दा

भाजपा नेता ने रायचूर क्षेत्र में खरीदे गए ज्वार के कथित बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने रायथा मोर्चा के अध्यक्ष नादहल्ली के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि किसानों को करीब 145 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान डेयरी फार्मिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसानों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध नहीं करा रही है। एससीपी-टीएसपी निधि के इस्तेमाल पर सवाल विजयेंद्र ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित एससीपी और टीएसपी निधि के इस्तेमाल को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन निधियों का उपयोग अन्य विभागों की योजनाओं में किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इन निधियों को उनके निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप खर्च करने की मांग की। बेल्लारी चलो पदयात्रा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा का मुख्य मुद्दा सूखा, किसान संकट और राज्य सरकार की कृषि नीतियों को लेकर विपक्ष का विरोध है। विजयेंद्र की मांगों के केंद्र में फिलहाल तीन प्रमुख मुद्दे हैं—सूखे पर विधानसभा का विशेष सत्र, किसानों के 5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण की माफी और सिंचाई परियोजनाओं को गति देना। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और किसानों को राहत देने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है।

शत्रुंजय-गिरनार दर्शन का सौभाग्य

भारतार्थ खबर Bhaaarataarth.com

बेंगलुरु, 3 सितंबर 2026। श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, बसवनगुड़ी के तत्वावधान में आयोजित चातुर्मास प्रवचन के दौरान प. पूज्य साध्वी श्री प्रियश्रद्धांजना श्री जी म. सा. ने कहा कि शत्रुंजय और गिरनार जैसे महान तीर्थों की स्पर्शना एवं पूजा का अवसर प्राप्त होना जीवों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। साध्वी जी ने ध्यान शतक ग्रंथ की विवेचना करते हुए कहा कि योग सिद्धियों और विशेष लब्धियों का उपयोग सांसारिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति अथवा चमत्कार प्रदर्शित कर प्रसिद्धि हासिल करने के लिए किया जाए तो यह साधक के आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकता है। ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति के संसार भ्रमण को बढ़ाती है और उसे मोक्ष रूपी अंतिम लक्ष्य से दूर कर सकती है। उन्होंने कहा कि सिद्धियों का उपयोग धर्म रक्षा, तीर्थ रक्षा और जिनशासन की सुरक्षा जैसे श्रेष्ठ कार्यों के लिए होना चाहिए। वर्तमान समय में देव तत्व की प्रत्यक्ष उपस्थिति न होने के बावजूद जिनशासन की परंपरा आचार्य, उपाध्याय, साधु और साध्वी भगवंतों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रवचन में महाविदेह क्षेत्र का उल्लेख करते हुए साध्वी जी ने बताया कि वहां परमात्मा अपने प्रवचनों में भरत क्षेत्र के जीवों के विशेष सौभाग्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्हें इस संसार के दो महान तीर्थों—शत्रुंजय और गिरनार—की स्पर्शना और पूजा करने का अवसर प्राप्त है। उन्होंने आगाह किया कि व्यक्ति को प्राप्त लब्धियों का उपयोग यदि केवल संसार में प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से अहितकारी हो सकता है। गृद्धि और क्षुधा से जुड़े दुर्ध्यान के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आषाढ़भूति का दृष्टांत प्रस्तुत किया और कहा कि भरत महाराजा का अभिनय करते-करते उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साध्वी जी ने कहा कि जानबूझकर किया गया पाप और दुर्ध्यान जीव के भव भ्रमण को बढ़ा सकता है। उन्होंने आगामी पर्युषण महापर्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्व बाहरी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल और शुद्ध करने का लोकोत्तर अवसर है। उन्होंने जैन रामायण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है, जिसकी प्रत्येक शिक्षा को आत्मसात करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

हरिप्रसाद की सिद्धारमैया से मुलाकात, संगठन पर मंथन

भारतार्थ खबर Bhaaarataarth.com

बेंगलुरु, 3 सितंबर 2026। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यसमिति (CWC) के सदस्यों तथा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने तथा कार्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। नेताओं ने संगठन की

मौजूदा स्थिति और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की।

हरिप्रसाद की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से हुई यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब कर्नाटक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने पर कांग्रेस का जोर है। बैठक में किन-किन मुद्दों पर अंतिम निर्णय हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा को पार्टी के भीतर समन्वय और रणनीतिक तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कृष्ण से सीखें सफल नेतृत्व की कला

भारतार्थ खबर
Bhaaarataarth.com

बेंगलुरु, 3 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागरजी महाराज ने विशेष प्रेरक प्रवचन में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों के माध्यम से सफल नेतृत्व, पुरुषार्थ, विनम्रता, रणनीतिक सोच, सही निर्णय क्षमता और कर्मयोग के सूत्रों को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ऑनलाइन माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं तक पहुंचे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेषझद सक्सेसफुल लीडर विषयक प्रवचन में मुनि श्री ने कहा कि महापुरुषों के जीवन को केवल धार्मिक कथा या इतिहास के रूप में देखने के बजाय उनकी शिक्षाओं को वर्तमान जीवन की चुनौतियों से जोड़ना आवश्यक है। महापुरुषों के जीवन से आत्म-परिवर्तन की प्रेरणा मुनि श्री वीरसागरजी महाराज ने कहा कि लोग भगवान श्रीकृष्ण, भगवान राम और अन्य महापुरुषों के जीवन प्रसंगों को पढ़ते और सुनते तो हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को अपने व्यवहार और निर्णयों में उतारने का प्रयास अपेक्षाकृत कम करते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है, जब व्यक्ति महापुरुषों के संघर्षों में अपने संघर्षों को देखता है और उनके अनुभवों से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन

प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों और जीवनियों का उद्देश्य केवल ज्ञान संग्रह नहीं, बल्कि आत्म-परिवर्तन होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं, पुरुषार्थ बनाता है भविष्य भगवान श्रीकृष्ण के जन्म प्रसंग का उल्लेख करते हुए मुनि श्री ने कहा कि महान व्यक्तित्व हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बनते। कठिनाइयां जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन व्यक्ति का पुरुषार्थ ही उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि सफल व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उपलब्ध संसाधनों और अवसरों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। सफल नेतृत्व का पहला गुण अपने निर्णयों और कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। रणछोड़ का संदेशः हर पीछे हटना हार नहीं प्रवचन में भगवान श्रीकृष्ण के रणछोड़ नाम के संदर्भ में मुनि श्री ने कहा कि हर परिस्थिति में संघर्ष करते रहना ही बुद्धिमानी नहीं है। कई बार परिस्थिति का सही आकलन कर समय रहते अपनी रणनीति बदलना अधिक दूरदर्शिता का परिचायक होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कई बार अहंकार के कारण गलत निर्णय पर अड़ा रहता है। जबकि गलती स्वीकार करना, माफी मांगना और आवश्यकता पड़ने पर अपना निर्णय बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और आत्मबल का प्रतीक है। मुनि श्री ने कहा कि पीछे हटना हमेशा पराजय नहीं होता, बल्कि कई बार भविष्य की बड़ी सफलता की तैयारी हो सकता है। यह सिद्धांत व्यापार, नौकरी, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। विनम्रता से बनता है सच्चा नेता भगवान श्रीकृष्ण के गुरुकुल जीवन और सुदामा से उनकी मित्रता का उल्लेख करते हुए मुनि श्री वीरसागरजी महाराज ने कहा कि नेतृत्व की पहचान पद या अधिकार से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार से होती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक महानता सुविधाएं प्राप्त करने में नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार के कार्य को सहजता से करने में है। सच्चा नेता वही है, जो लोगों के बीच सहजता से उपलब्ध रहे, उनकी बात सुने और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की वास्तविक ऊंचाई उसके पदनाम से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की ऊंचाई से तय होती है। कर्म पर ध्यान, परिणाम में समभाव प्रवचन के दौरान मुनि श्री ने गीता के कर्मयोग संदेश की आधुनिक जीवन के संदर्भ में व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति को लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन कार्य करते समय उसकी पूरी ऊर्जा केवल परिणाम की चिंता में नष्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए तैयारी, अनुशासन, निरंतर प्रयास और कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता तनाव और भय पैदा करती है, जिससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। मुनि श्री ने सफल जीवन का सूत्र बताते हुए कहा कि व्यक्ति को लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए, प्रयास पूर्ण करना चाहिए और परिणाम को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता मिलने पर अहंकार नहीं और अपेक्षित परिणाम न मिलने पर निराशा नहीं—यही संतुलित और सार्थक जीवन का आधार है। आधुनिक जीवन के लिए प्रेरक संदेश मुनि श्री वीरसागरजी महाराज ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से आधुनिक समाज को नेतृत्व और जीवन प्रबंधन के अनेक महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। सफल व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय पुरुषार्थ करता है, सच्चा नेता अहंकार के कारण गलत निर्णय पर नहीं अड़ता और वास्तविक महानता विनम्रता तथा आत्मीयता में दिखाई देती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आान किया कि महापुरुषों के जीवन को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को अपने व्यवहार और निर्णयों का हिस्सा बनाएं। मुनि श्री ने कहा कि जब व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय पाने का संकल्प करता है, अहंकार छोड़कर सही निर्णय लेना सीखता है, विनम्रता अपनाता है और परिणामों की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्म में पूर्ण समर्पण करता है, तभी वह जीवन का वास्तविक और सफल नेता बनता है। समाचार प्रेषकः विपिन कुमार जैन, बेंगलुरु

कुमारस्वामी को चालुवरैयास्वामी की खुली बहस की चुनौती

भारतार्थ खबर
Bhaaarataarth.com

बेंगलुरु, 3 सितंबर 2026। जल संसाधन मंत्री एन. चालुवरैयास्वामी ने केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे हिट एंड रन की राजनीति में विश्वास नहीं करते और यदि कुमारस्वामी के पास उनके खिलाफ कोई तथ्य हैं तो वे विधान सौध अथवा किसी टेलीविजन चैनल पर आमने-सामने चर्चा के लिए आएं। विधान सौध में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में चालुवरैयास्वामी ने अपने दिल्ली दौरे का बचाव करते हुए कहा कि वे राज्य की सिंचाई संबंधी समस्याओं और लंबित परियोजनाओं पर चर्चा के लिए दो दिन दिल्ली में थे। उन्होंने कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के रूप में पिछले ढाई वर्षों में उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया, इसका जवाब उन्हें सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। मंत्री ने कृष्णा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से प्रस्तावित धनराशि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाले आवश्यक धन को दिलाने में पहले सफलता हासिल की जानी चाहिए। किसानों और सिंचाई परियोजनाओं पर जोर चालुवरैयास्वामी ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मेकेदातु परियोजना को लेकर केंद्र के स्तर पर हुई चचाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय जल आयोग और राज्य के अपर मुख्य सचिव के साथ परियोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु को नुकसान नहीं होगा। उनके अनुसार, परियोजना से कर्नाटक में काबिनी और कृष्णराज सागर (KRS) जलाशयों पर दबाव कम करने तथा कावेरी के पानी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती

है। महादयी परियोजना को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से अलग बैठक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के स्तर पर आवश्यक सहयोग मिलने पर राज्य सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर कानूनी लड़ाई का दावा कावेरी जल विवाद का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ते से भी संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में भी तमिलनाडु को पानी छोड़ा गया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से 12,000 क्यूसेक के बजाय 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आगामी सुनवाई में तमिलनाडु को पानी छोड़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। KPSC में गड़बड़ी की जांच के पक्ष में कुमारस्वामी द्वारा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर चालुवरैयास्वामी ने कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार जांच में सहयोग करेगी। उन्होंने KPSC के पूर्व अध्यक्ष के निलंबन का उल्लेख करते हुए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने भाजपा-जेडीएस के पूर्व कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) की मौजूदा व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि वहां कार्यरत अधिकारी सक्षम हैं। साइबर शिकायत और पूर्व सैनिक से जुड़े मामले पर भी बोले

राज्य की एक सरकारी वेबसाइट के कथित हैक होने के मामले में मंत्री ने कहा कि साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे एक पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के सवाल पर चालुवरैयास्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह के व्यवहार के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है और यदि पुलिस की ओर से अनुचित कार्रवाई हुई है तो संबंधित विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

TTD अधिकारी पर ACB का शिकंजा, 5 करोड़ की संपत्ति जब्त

भारतार्थ खबर Bhaaarataarth.com

तिरुपति, 3 सितंबर 2026। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Dy.EO) मेंडु लोकनाधम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। अउइ ने अधिकारी से जुड़े ठिकानों और उनके रिश्तेदारों के परिसरों समेत तिरुपति जिले में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति और कीमती सामान मिलने का दावा किया गया है। ACB के अनुसार तलाशी के दौरान करीब 2 किलोग्राम सोना, 6.5 किलोग्राम चांदी और 12.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषणों तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी जांच एजेंसी ने जब्त किए हैं। CBI से मिली जानकारी के बाद शुरू हुई जांच ACB की ओर से बुधवार देर रात जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्रवाई की शुरूआत केंद्रीय जांच ब्यूरो (उइक) से मिली जानकारी के आधार पर हुई। बताया गया कि ४ उइककी तिरुमाला तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान कुछ ऐसी जानकारी सामने आई थी, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए आंध्र प्रदेश अउइ के साथ साझा किया गया। इसी क्रम में अउइ ने पहले 22 अप्रैल 2026 को TTD के पूर्व चेयरमैन वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के निजी सहायक के. चिन्ना अप्पन्ना के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामला दर्ज किया था। इसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर Dy.एड मेंडु लोकनाधम के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार

निरोधक कानून के तहत मामला ACB ने लोकनाधम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में 2018 में किए गए संशोधनों के तहत धारा 13(2) और 13(1)() में मामला दर्ज किया है। यह मामला क्राइम नंबर 06/RCA-TCT/2026 के रूप में दर्ज बताया गया है। जांच एजेंसी ने बुधवार सुबह चार ठिकानों पर तलाशी ली। इस दौरान विभिन्न संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है। परिवार के नाम पर संपत्तियों की भी जांच ACB के मुताबिक तलाशी में मिले दस्तावेजों से ऐसी संपत्तियों का पता चला है, जिनमें कुछ कथित तौर पर अधिकारी के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। इनमें तिरुपति के पीके लेआउट स्थित एक मकान, गोल्लावानीगुंटा क्षेत्र में दो आवासीय भूखंड और एक भवन, वडमालापेटा मंडल के पादिरेडु अरण्यम गांव में भूखंड तथा श्रीनिवास नगर क्षेत्र में एक आवासीय भूखंड शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार श्रीनिवास नगर की संपत्ति अधिकारी के बेटे के नाम पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त अधिकारी और उनके बेटे के नाम पर चार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से संबंधित जानकारी भी जांच के दौरान सामने आई है। रिश्तेदार के घर से भी मिला संपत्ति दस्तावेज ACB ने बताया कि अधिकारी के जीजा के घर की तलाशी के दौरान करीब 31.98 लाख रुपये मूल्य की एक संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिला। यह दस्तावेज अधिकारी की पत्नी और अन्य व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर होने की जानकारी दी गई है। एजेंसी का कहना है कि अब तक सामने आई चल-अचल संपत्तियों, आभूषणों, नकदी और अन्य कीमती सामान का कुल अनुमानित मूल्य करीब 5 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी ACB ने स्पष्ट किया है कि तलाशी और जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। जब्त दस्तावेजों और संपत्तियों की वैधता, आय के स्रोत तथा अधिकारी की घोषित आय के साथ उनकी तुलना की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद संपत्ति में से कितनी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है और उसके संबंध में आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अउइ की कार्रवाई को एक जांच के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों के बाद ही होगी।

हैदराबाद में नकली नोटों का खेल बेनकाब, तीन गिरफ्तार

भारतार्थ खबर
Bhaaarataarth.com

हैदराबाद, 3 सितंबर 2026। हैदराबाद में नकली भारतीय मुद्रा तैयार कर उसे बाजार में चलाने के कथित नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। शमशाबाद जोन कमिश्नर की टास्क फोर्स और बालापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक फूड डिलीवरी कर्मी, एक बाइक-टैक्सी चालक और एक ऑटो चालक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,124 कथित नकली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल अंकित कीमत 2,91,100 रुपये बताई गई है। बरामद नोट 500, 200 और 100 रुपये के मूल्यवर्ग के हैं। मामले में एक अन्य कथित सहयोगी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। YouTube और Instagram से तरीका सीखने का दावा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने नकली नोट तैयार करने का तरीका किसी संगठित गिरोह से सीधे सीखने के बजाय YouTube और Instagram पर उपलब्ध वीडियो देखकर सीखा। इसके बाद कथित तौर पर प्रिंटर, स्कैनर, कागज और अन्य सामग्री जुटाकर नकली नोट तैयार करने का काम शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार रामावथ रमु उर्फ मोहम्मद (36), रामावथ मोतीलाल (35) और रामावथ गांधी (19) इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों को तेलंगाना के वड्डीपटला स्थित चिंतल थांडा का निवासी बताया गया है। रमु फूड डिलीवरी का काम करता था, मोतीलाल बाइक-टैक्सी चालक और गांधी ऑटो चालक है। चौथे आरोपी के रूप में नागोल-बंडलगुड़ा निवासी सुधीर जॉन चेला उर्फ वामशी का नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताया गया है। घर में तैयार होता था नकली नोटों का सेटअप जांच के दौरान पुलिस ने नकली करेंसी तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण और सामग्री बरामद करने का दावा किया है। इनमें कलर प्रिंटर, स्कैनर, लैमिनेटर, पेपर कटर, विभिन्न रंगों के तरल पदार्थ, कागज तथा कथित वॉटरमार्क पेपर सहित अन्य सामान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने असली नोटों की कुछ विशेषताओं की नकल करने का प्रयास किया था। हालांकि, बरामद सामग्री और तैयार नोटों की वास्तविक प्रकृति की विस्तृत जांच अब जांच एजेंसियों के स्तर पर की जानी है। बाजार में छोटी मात्रा में चलाने का आरोप पुलिस के अनुसार कथित तौर पर तैयार किए गए नकली नोटों को एक साथ बड़ी मात्रा में बाजार में उतारने के बजाय छोटी-छोटी रकम के रूप में चलाने की कोशिश की जाती थी। इसके लिए शराब की दुकानों और सब्जी बाजारों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक यह गतिविधि विशेष रूप से रात के समय की जाती थी। पुलिस के अनुसार रमु का भतीजा गांधी भी कथित तौर पर नकली नोटों को बाजार में चलाने के प्रयास में शामिल था। इसी दौरान पुलिस को नेटवर्क के बारे में सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया गया। 1,124 नोटों में 500, 200 और 100 रुपये के नोट पुलिस के मुताबिक बरामद नकली नोटों में 437 नोट 500 रुपये के, 39 नोट 200 रुपये के और 648 नोट 100 रुपये के हैं। इनकी कुल अंकित कीमत 2,91,100 रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने कथित तौर पर नोटों की नकल के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ असली नोट भी बरामद किए हैं। आर्थिक परेशानी से अपराध की ओर जाने का पुलिस का दावा जांच अधिकारियों के अनुसार रमु कथित तौर पर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने अपने रिश्तेदार मोतीलाल के साथ मिलकर आसानी से पैसा कमाने के लिए नकली नोट तैयार करने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद दोनों ने आवश्यक सामग्री जुटाई और इसके बाद नकली मुद्रा तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ऑनलाइन वीडियो में उपलब्ध संपर्क के पीछे कौन व्यक्ति था और क्या इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच में और जानकारी सामने आने की संभावना है। मोबाइल फोन और वाहन भी जब्त पुलिस ने कार्रवाई के दौरान प्रिंटर और स्कैनर सहित कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरणों के अलावा मोबाइल फोन और दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। बरामद सामग्री को जांच का हिस्सा बनाया गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर नकली नोटों की तैयारी और उनके प्रसार का सिलसिला कब से चल रहा था तथा अब तक कितनी मुद्रा बाजार में पहुंचाई गई। नकली मुद्रा अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के लिए गंभीर चुनौती है। हैदराबाद की यह कार्रवाई यह भी रेखांकित करती है कि इंटरनेट पर उपलब्ध आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी सामग्री का दुरुपयोग कानून-व्यवस्था के लिए नई चुनौती बन सकता है। हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

मुंबई, 3 सितंबर 2026। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरूआत सकारात्मक रुख के साथ हुई। शुरूआती कारोबार में निवेशकों की खरीदारी से प्रमुख सूचकांकों में मजबूती दिखाई दी। सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक चढ़कर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब पहुंच गया। सुबह करीब 10:06 बजे सेंसेक्स 76,864.35 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद स्तर की तुलना में लगभग 294 अंक की बढ़त दर्शाता है। वहीं, निफ्टी 89.60 अंक मजबूत होकर 24,004.05 के स्तर के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। शुरूआती कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव देखने को मिला था, लेकिन गुरुवार को बाजार खुलते ही निवेशकों की खरीदारी ने माहौल बदल दिया। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि शुरूआती तेजी को पूरे कारोबारी सत्र की दिशा मानना जल्दबाजी होगी। शेयर बाजार में दिनभर वैश्विक और घरेलू संकेतों के आधार पर उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बैंकिंग शेयरों ने दिखाई मजबूती शुरूआती कारोबार में बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में विशेष मजबूती देखने को मिली। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार निफ्टी बैंक करीब 0.94 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,709.10 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में भी करीब 0.30 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों में खरीदारी और बिकवाली का मिश्रित रुख देखने को मिला, जिससे बाजार में कारोबारी गतिविधियां सक्रिय बनी रहीं। सेंसेक्स 76,800 के पार पहुंचा गुरुवार सुबह के कारोबार में सेंसेक्स ने 76,800 अंक के स्तर के ऊपर मजबूती दिखाई। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की बढ़त ने निवेशकों के बीच सकारात्मक धारणा को बल दिया। दूसरी ओर, निफ्टी का 24,000 अंक के आसपास पहुंचना बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, तकनीकी और कारोबारी स्तर पर इन सूचकांकों की आगे की चाल पूरे दिन निवेशकों की निगाहों में रहेगी। रुपये की चाल पर भी निवेशकों की नजर शेयर बाजार के साथ-साथ मुद्रा बाजार की गतिविधियां भी चर्चा में रहीं। शुरूआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 94.47 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया और इसमें पिछले स्तर की तुलना में कुछ मजबूती दर्ज की गई। रुपये की स्थिति का प्रभाव आयात आधारित कंपनियों, निर्यातकों और विदेशी निवेश से जुड़े बाजार क्षेत्रों पर पड़ सकता है। ऐसे में निवेशक शेयर बाजार के साथ मुद्रा बाजार की गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैश्विक संकेतों का रहेगा असर भारतीय शेयर बाजार की दिशा केवल घरेलू घटनाक्रम से तय नहीं होती। एशियाई बाजारों की चाल, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की धारणा, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी बाजारों के संकेतों का भी भारतीय बाजार पर प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम आने वाले कारोबारी सत्रों में निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। दिनभर के कारोबार पर रहेगी नजर बाजार में शुरूआती तेजी के बाद अब निवेशकों की नजर कारोबार समाप्त होने तक सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति पर रहेगी। बाजार किस स्तर पर बंद होता है, इससे आने वाले कारोबारी सत्रों की धारणा को लेकर संकेत मिल सकते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक दिन की तेजी या गिरावट के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय न लें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, कारोबार, जोखिम और बाजार परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। फिलहाल गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरूआत सकारात्मक रही है। सेंसेक्स में मजबूत बढ़त और निफ्टी का 24,000 अंक के आसपास पहुंचना बाजार में खरीदारी के रुझान को दर्शाता है। हालांकि, दिनभर के कारोबार में उतार-चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। समाचार प्रेषक: अशोक कुमार सिंह, बेंगलुरु

यूपी में बाढ़ का कहर, 16,784 लोगों को बचाया

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

उत्तर प्रदेश, 3 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति से जनजीवन प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों और राहत दलों द्वारा अब तक 16,784 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रभावित इलाकों में जलस्तर और स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जहां पानी बढ़ने से लोगों की सुरक्षा को खतरा है, वहां राहत दलों की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य जारी है। कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित बाढ़ के कारण अनेक इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलभराव और बाढ़ की स्थिति से आवागमन में कठिनाई पैदा हुई है, जबकि प्रभावित परिवारों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने की है।

संबंधित विभागों की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं। राहत-बचाव दल लगातार सक्रिय बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। पानी से घिरे क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना राहत अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। लोगों को जलभराव वाले रास्तों, तेज बहाव वाले क्षेत्रों और असुरक्षित स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को प्रशासन और राहत-बचाव एजेंसियों से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। प्रशासनिक टीमें जलस्तर और मौसम की स्थिति के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरतमंद परिवारों तक राहत सहायता पहुंचाना है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा स्थिति सामान्य होने तक प्रशासन की निगरानी बनी रहने की बात कही जा रही है। समाचार प्रेषक: अशोक कुमार सिंह, बेंगलुरु

बारिश में धंसी 90 फीट सड़क

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बाराबनी (पश्चिम बंगाल), 3 सितंबर 2026। पश्चिम बंगाल के बाराबनी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद एक प्रमुख सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नूनी मोड़ से मदनपुर को जोड़ने वाली सड़क का करीब 80 से 90 फीट हिस्सा जमीन में धंस गया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग पर आवाजाही रोक दी। बताया जा रहा है कि सड़क का प्रभावित हिस्सा करीब 6 से 7 फीट तक नीचे धंस गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मौके पर बांस की बैरिकेडिंग कर लोगों और वाहनों को धंसे हुए हिस्से से दूर रखने की व्यवस्था की। एक साल पहले बनी थी सड़क स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सड़क करीब एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। स्थानीय भाजपा नेता सुजीत मंडल ने सड़क निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया है। हालांकि, सड़क निर्माण की लागत और गुणवत्ता से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। प्रशासन द्वारा तकनीकी जांच के बाद ही सड़क धंसने के कारण और निर्माण संबंधी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क धंसने से पहले सामान्य स्थिति में थी, लेकिन लगातार हुई भारी बारिश के बाद अचानक इसका एक बड़ा हिस्सा नीचे चला गया। बारिश या तालाब, क्या है धंसने की वजह? सड़क धंसने के कारण को लेकर फिलहाल अलग-अलग आशंकाएं सामने आ रही हैं। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी नरम हो गई होगी, जिससे सड़क की संरचना कमजोर पड़ गई। वहीं, स्थानीय भाजपा नेता सुजीत मंडल ने सड़क के समीप स्थित एक बड़े और गहरे तालाब को भी संभावित कारण बताया है। हालांकि, सड़क धंसने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की तकनीकी जांच के बाद ही इस घटना के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। रात में मिली सूचना, पहुंचा प्रशासन स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क धंसने की जानकारी प्रशासन को रात के समय मिली। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की कार्रवाई शुरू की गई। ग्रामीणों की सहायता से धंसे हुए हिस्से के आसपास बांस की बैरिकेडिंग की गई। इसका उद्देश्य लोगों को खतरे वाले क्षेत्र में जाने से रोकना और किसी संभावित दुर्घटना से बचाव करना है। फिलहाल सड़क के प्रभावित हिस्से से वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। मरीजों और आम लोगों की बढ़ी परेशानी यह सड़क आसपास के गांवों और स्थानीय क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बताई जा रही है। रोजमर्रा के आवागमन के अलावा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और एंबुलेंस की आवाजाही के लिए भी इस मार्ग का उपयोग किया जाता रहा है। सड़क बंद होने के बाद स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ रहे हैं। विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों और एंबुलेंस की आवाजाही को लेकर चिंता जताई जा रही है। स्थानीय भाजपा नेता सुजीत मंडल ने प्रशासन से प्रभावित लोगों के लिए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था और सड़क की मरम्मत की मांग किए जाने की बात कही है। आवासीय क्षेत्र के करीब धंसी सड़क स्थानीय निवासी तारक नाथ मंडल के अनुसार धंसा हुआ हिस्सा उनके घर के काफी निकट है। उन्होंने बताया कि सड़क की वर्तमान स्थिति से आसपास रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों और रोजाना काम पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

नालागढ़ फार्मा यूनिट पर NCB की दबिश

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

सोलन, 3 सितंबर 2026। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में कथित तौर पर नशीली और नियंत्रित दवाओं के उत्पादन तथा आपूर्ति को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। नालागढ़ के जगातखाना के निकट स्थित सारिका बायोटेक में एनसीबी चंडीगढ़ की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद किए जाने का दावा किया है। जांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान 2,000 किलोग्राम से अधिक टेपेंटाडोल और करीब 25 लाख अन्य दवाएं बरामद होने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी के अनुसार, संबंधित उद्योग के पास टेपेंटाडोल के उत्पादन अथवा इस्तेमाल की आवश्यक अनुमति नहीं थी। हालांकि, बरामद सामग्री की प्रकृति, मात्रा और कथित उल्लंघनों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। उद्योग सील, मालिक हिरासत में एनसीबी ने कार्रवाई के बाद संबंधित औद्योगिक परिसर को सील कर दिया है। इसके साथ ही उद्योग से जुड़े मालिक के गोदामों पर भी तलाशी अभियान चलाए जाने की जानकारी है। मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी अब बरामद दवाओं के स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया और संभावित वितरण नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि दवाओं का

कथित रूप से अनधिकृत उत्पादन या भंडारण हुआ था, तो उनका वितरण किन माध्यमों से और किन स्थानों तक किया गया। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है। दवा नियामक व्यवस्था पर उठे सवाल एनसीबी की कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश की दवा नियामक व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि यदि उद्योग में ऐसी दवाओं का उत्पादन या भंडारण नियमों के विपरीत हो रहा था, तो संबंधित नियामक तंत्र को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली। हालांकि, इस संबंध में किसी विभाग या अधिकारी पर निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक जांच और दस्तावेजी तथ्यों का सामने आना जरूरी है। संबंधित राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। देश के अन्य हिस्सों तक सप्लाई की आशंका जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू संभावित सप्लाई नेटवर्क भी है। यदि जांच में अनधिकृत उत्पादन या दवाओं के डायवर्जन की पुष्टि होती है, तो एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास करेंगी कि बरामद अथवा पहले तैयार की गई सामग्री कहीं दूसरे राज्यों तक तो नहीं पहुंची। फिलहाल देशभर में कथित आपूर्ति की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस पहलू को जांच के दायरे में मौजूद संभावना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। बीबीएन में पहले भी सामने आए मामले हिमाचल का बीबीएन क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक और फार्मा केंद्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में दवा निर्माण इकाइयां संचालित होती हैं। ऐसे में किसी इकाई से संबंधित कथित अनियमितता का मामला सामने आने पर निगरानी और अनुपालन व्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। पिछले वर्षों में भी हिमाचल के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से ट्रामाडोल, कोडिन आधारित दवाओं और कथित नकली या अनधिकृत दवाओं से जुड़े मामले सामने आने की रिपोर्टें रही हैं। इनमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने समय-समय पर कार्रवाई की है। मई 2024 में भी हिमाचल से जुड़े कुछ फार्मा प्रतिष्ठानों पर मनोचिकित्सकीय अथवा नियंत्रित दवाओं की कथित अवैध आपूर्ति के नेटवर्क को लेकर कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। अगस्त 2024 में कोडिन आधारित कफ सिरप के कथित डायवर्जन मामले में भी जांच एजेंसी की कार्रवाई चर्चा में रही। इसी तरह 2025 और 2026 में भी बीबीएन क्षेत्र में दवा निर्माण और कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में नियामक कार्रवाई की जानकारी सामने आती रही है। जांच के नतीजे पर टिकी नजर सारिका बायोटेक मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामद दवाएं और टेपेंटाडोल किस उद्देश्य से रखे गए थे तथा उनका स्रोत और संभावित गंतव्य क्या था। एनसीबी की जांच से उत्पादन, दस्तावेजों, लाइसेंस, भंडारण और वितरण से संबंधित कई पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। यदि किसी प्रकार का गैरकानूनी उत्पादन या वितरण प्रमाणित होता है तो संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है।

शिव महिमा के बीच गूंजा राम जन्मोत्सव

छायाचित्र: किशोर कुमार दफ्तरी

भारतार्थ खबर, बेंगलुरु संवाददाता
अशोक कुमार
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 3 सितंबर 2026। फूलों की नगरी बेंगलुरु में प्रिंसेज श्राइन, पैलेस ग्राउंड के गेट नंबर-9 पर आयोजित संगीतमय श्रीराम कथा के तीसरे दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। परम पूज्य श्री राजन जी महाराज के श्रीमुख से भगवान शिव की महिमा और प्रभु श्रीराम के दिव्य जन्म प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन सुनकर श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो उठे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य यजमान द्वारा व्यासपीठ के पूजन एवं आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात कथाव्यास ने गोस्वामी तुलसीदास रचित श्रीरामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भगवान शिव की महिमा तथा श्रीरामावतार के प्रसंगों का भावपूर्ण विवेचन किया। भक्ति से निर्मल होता है मन

कथा के प्रथम सत्र में कथाव्यास ने भगवान शिव के अलौकिक स्वरूप और उनकी भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल से शरीर की बाहरी शुद्धि संभव है, लेकिन मन और अंतरात्मा की निर्मलता का मार्ग ईश्वर की सच्ची भक्ति से होकर गुजरता है। उन्होंने कैलास पर्वत पर भगवान शिव द्वारा माता पार्वती के संशय का समाधान करते हुए श्रीराम कथा के रहस्य का वर्णन किए जाने वाले प्रसंग का उल्लेख किया। कथाव्यास ने कहा कि परमात्मा एक ही है, जो निर्गुण-निराकार स्वरूप में भी है और भक्तों के प्रेम से सगुण-साकार रूप भी धारण करता है। धर्म की रक्षा और सज्जनों के कल्याण के लिए भगवान समय-समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। पुत्रकामेष्टि यज्ञ से राम जन्म तक का भावपूर्ण प्रसंग

कथा के द्वितीय सत्र में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्रकामेष्टि यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। संतान प्राप्ति की कामना से गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा पर ऋष्यशृंग ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ का आयोजन किया गया। कथा के अनुसार यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव दिव्य प्रसाद लेकर प्रकट हुए। राजा दशरथ ने प्रसाद स्वरूप प्राप्त चरु को माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा में श्रद्धापूर्वक वितरित किया। इसके बाद श्रीराम जन्म की कथा के साथ संपूर्ण पंडाल भक्ति और उल्लास के वातावरण में डूब गया। सोहर गीतों से गूंज उठा कथा पंडाल

जैसे ही प्रभु श्रीराम के जन्म का प्रसंग आया, कथा स्थल भक्ति संगीत और मंगलध्वनियों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और सोहर गीतों की मधुर प्रस्तुतियों पर भक्तिमय उल्लास का वातावरण बन गया। अनेक श्रद्धालु भजन और मंगल गीतों की धुन पर झूमते नजर आए। सांस्कृतिक चेतना और मर्यादित जीवन का संदेश

आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री शैलेश मिश्रा ने कहा कि श्रीराम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का जीवन सत्य, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की प्रेरणा देता है। युवाओं को इन आदर्शों से जोड़कर उन्हें जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से परिवार सहित कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की।

ट्रस्ट के सचिव श्री रोहित उपाध्याय ने बताया कि कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा श्रवण किया। उनके अनुसार, लगभग 2,000 भक्तों की उपस्थिति ने आयोजन के प्रति लोगों की आस्था और उत्साह को दर्शाया। अगले दिनों में विवाह प्रसंगों की तैयारी आयोजकों के अनुसार कथा के आगामी सत्रों में भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह प्रसंग सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। वहीं, श्रीराम कथा के चौथे दिन कथावाचक श्री प्रवीण पांडे जी द्वारा धनुष भंग एवं श्रीसीताराम विवाह प्रसंग का वर्णन किए जाने की जानकारी दी गई है। आयोजन की व्यवस्थाओं में श्री शैलेश मिश्रा, श्री रोहित उपाध्याय, श्री धीरज राज, श्री आदेश, श्रीमती गौरी मिश्रा, श्री प्रवीण पांडेय, श्री लाल बाबू पांडेय, श्री संजय सिंह उज्जैन, श्री प्रेम प्रकाश पांडे सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

उत्तराखंड में 16 बिल्डरों पर जीएसटी छापा, 7.73 करोड़ जमा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

देहरादून, 3 सितंबर 2026। उत्तराखंड के रियल एस्टेट क्षेत्र में कथित कर अनियमितताओं के खिलाफ राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) और अन्य जांच इकाइयों ने गुरुवार को देहरादून सहित हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में 16 बिल्डरों से जुड़े व्यावसायिक परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान मौके पर ही 7.73 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई है। राज्य कर विभाग के मुताबिक यह कार्रवाई आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देश पर की गई। अभियान में 16 टीमों के साथ करीब 55 अधिकारी शामिल रहे। तलाशी के दौरान विभिन्न फर्मों के व्यावसायिक परिसरों से बिक्री, भुगतान, निर्माण और कर संबंधी महत्वपूर्ण अभिलेख तथा कारोबारी रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए हैं। विभाग का कहना है कि जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद संबंधित फर्मों की वास्तविक कर देयता का आकलन किया जाएगा। जांच में यदि अतिरिक्त कर चोरी या अन्य अनियमितता सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जीएसटी बचाने के कथित तौर-तरीकों पर नजर राज्य कर विभाग की जांच का प्रमुख केंद्र रियल एस्टेट परियोजनाओं में लागू जीएसटी व्यवस्था और उसके संभावित दुरुपयोग से जुड़ा है। विभाग के अनुसार किफायती आवास पर एक प्रतिशत और अन्य आवासीय फ्लैटों पर पांच प्रतिशत जीएसटी की व्यवस्था है। पांच प्रतिशत वाली व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं लिया जा सकता। जांच एजेंसी ऐसे मामलों की पड़ताल कर रही है, जिनमें आरोप है कि खरीदार से फ्लैट की पूरी या अधिकांश राशि पहले ही प्राप्त कर ली जाती है, जबकि संपत्ति की रजिस्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कराई जाती है। विभाग को आशंका है कि कुछ मामलों में लेनदेन को इस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हो सकता है कि बिक्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद हुई और उस पर जीएसटी देयता लागू न हो। हालांकि, प्रत्येक मामले में वास्तविक स्थिति दस्तावेजों की जांच और संबंधित लेनदेन के तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी। निर्माण फर्मों के जरिए आईटीसी की भी जांच जांच में बिल्डरों द्वारा अपनी या उनसे जुड़ी निर्माण फर्मों के माध्यम से परियोजनाओं का निर्माण कराने के तौर-तरीकों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। विभाग के अनुसार कुछ मामलों में निर्माण गतिविधियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी से जुड़े लेनदेन और इनपुट टैक्स क्रेडिट का परीक्षण किया जा रहा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं संबंधित निर्माण फर्मों से वास्तविक खरीद के बजाय केवल दस्तावेजों में खरीद दिखाकर अनुचित तरीके से आईटीसी का लाभ तो नहीं लिया गया। इस क्रम में वास्तविक खरीद, भुगतान, बिल, निर्माण कार्य और संबंधित दस्तावेजों के बीच तालमेल की जांच की जाएगी। 15 दिन तक जुटाई गई कारोबारी जानकारी राज्य कर विभाग के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र से अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। आयुक्त प्रतीक जैन के निर्देश पर बिल्डरों और उनसे संबंधित संविदाकार फर्मों के कारोबार से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। नोडल अधिकारी एवं संयुक्त आयुक्त अजय कुमार के समन्वय में प्रदेश की प्रवर्तन इकाइयों ने करीब 15 दिनों तक कारोबारियों के संव्यवहार और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं एकत्र कीं। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। बिक्री से लेकर रजिस्ट्री तक रिकॉर्ड की पड़ताल तलाशी के दौरान कब्जे में लिए गए दस्तावेजों की जांच में बिक्री समझौते, भुगतान का विवरण, रजिस्ट्री, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, निर्माण गतिविधियां, खरीद और आईटीसी से जुड़े रिकॉर्ड शामिल बताए गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर विभाग यह मिलान करेगा कि संबंधित परियोजनाओं में वास्तविक लेनदेन क्या था और विभाग को घोषित कारोबार एवं कर भुगतान में कोई अंतर तो नहीं है।

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at Maruthi"Plaza", No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, Advertisement 88676 89130 , RNI No. KNHIN/2026/A5540. E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026